CIN: U20299DL 1986NPL023253 | GST NO. 07AAACE1747M1Z.

प्रेस विज्ञप्ति

वस्त्र सचिव ने यूनाइटेड किंगडम में उच्च-स्तरीय आउटरीच का नेतृत्व किया

ईपीसीएच ने सीईपीसी और एचईपीसी के साथ मिलकर बायर एंगेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया ईपीसीएच के अध्यक्ष ने ब्रिटेन के खरीदारों से भारत - युके एफटीए से लाभ उठाने का आग्रह किया

नई दिल्ली/एनसीआर – 22 सितंबर 2025 – लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की सचिव, श्रीमती नीलम शमी राव ने खरीदारों और खरीद प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ईपीसीएच का प्रतिनिधित्व ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना और ईपीसीएच के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने किया । इस बैठक का उद्देश्य लक्षित जी2जी सहभागिता, केंद्रित बी2बी बैठकों और रोड शो के माध्यम से खरीदारों के साथ संबंधों को गहरा करके भारतीय उत्पादों के लिए ब्रिटिश बाजार में पहुँच को मजबूत करना था, ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की सचिव, श्रीमती नीलम शमी राव ने खरीदारों को संबोधित करते हुए, देश के समग्र निर्यात में भारतीय वस्त्र क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और देश से वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन, स्थिरता, ट्रेसेबिलिटी और विपणन पहलों के संबंध में उठाए जा रहे कदमों पर ज़ोर दिया। उन्होंने सभी खरीदारों से भारत-यूके व्यापार समझौते का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क में उल्लेखनीय कमी करके उसे नगण्य कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा कि, "ब्रिटेन के बाजार की मांग विकास के लिए एक सार्थक गुंजाइश प्रदान करती है और भारत-ब्रिटेन सीईटीए हमें प्रगतिशील टैरिफ कटौती, सरल उत्पत्ति नियमों और सुगम सीमा शुल्क के माध्यम से उस क्षमता को व्यापार में बदलने में मदद करता है भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को यूके में बेहतर दाम और जल्दी मंजूरी मिल सकेगी।

डॉ. खन्ना ने आगे कहा कि "हस्तशिल्प क्षेत्र में हस्तशिल्प निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई और कारीगर-आधारित उद्यमों के लिए गंभीर चुनौती पेश करने वाली कठोर परिश्रम-योग्य आवश्यकताओं को लेकर गहरी चिंताएँ हैं। हम सरकारी निकायों और उद्योग के हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करते हैं तािक एक व्यावहारिक अनुपालन ढाँचा विकसित किया जा सके जो वैश्विक स्थिरता लक्ष्य को पूरा करते हुए हमारे कारीगरों की रक्षा करे। हम वस्त्र सचिव की धैर्यपूर्वक सुनवाई की भी सराहना करते हैं और व्यावहारिक, एमएसएमई-अनुकूल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सीईटीए के अवसरों का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।"

ईपीसीएच के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने कहा कि "ईपीसीएच ने एचईपीसी और सीईपीसी के सहयोग से "भारत - हस्तिशल्प, हथकरघा और कालीनों की सोर्सिंग के लिए एक लाभदायक गंतव्य" विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती नीलम शमी राव उपस्थित रहीं। उनके साथ वस्त्र मंत्रालय की व्यापार सलाहकार श्रीमती शुभ्रा; वस्त्र समिति के सचिव श्री कार्तिकेय ढांडा; वस्त्र मंत्रालय के व्यापार निदेशक श्री अमित कुमार; तमिलनाडु सरकार की वस्त्र निदेशक श्रीमती आर. लिलता; ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना; एचईपीसी के अध्यक्ष श्री लिलत गोयल; सीईपीसी के अध्यक्ष श्री कुलदीप वट्टल; निफ्ट की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख डॉ. पेट्रीसिया सुमोद और अन्य विष अधिकारी उपस्थित रहे। इस सत्र में खरीदारों और सोर्सिंग पेशेवरों ने अवसरों का पता लगाने, बाजार के रुझानों के साथ तालमेल बिठाने और वैश्विक हस्तिशल्प मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की स्थिति की पृष्टि करने के लिए एक साथ आए।"

श्री रावत ने आगे कहा, "इस अवसर पर उपस्थित खरीदारों ने लॉजिस्टिक्स, बौद्धिक संपदा, डिजाइन संवेदनशीलता, ट्रेसेबिलिटी, ई-कॉमर्स और अन्य व्यावसायिक पहलुओं से संबंधित मुद्दों को उठाया तथा भारत-यूके एफटीए का लाभ उठाने के बारे में प्रबल उत्साह व्यक्त किया।"

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया कि हस्तिशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) देश से हस्तिशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न शिल्प समूहों में होम, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर और फैशन जूलरी एवं एक्सेसरीज उत्पादों के करोड़ों कारीगरों के हुनर को विश्व पटल पर पहचान दिलाना और उनके जादुई हाथों की छिव को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत का कुल हस्तिशिल्प निर्यात ₹33,123 करोड़ (यूएस \$3,918 मिलियन) रहा, जबिक केवल यूनाइटेड किंगडम को हस्तिशिल्प निर्यात ₹2,562.70 करोड़ (यूएस \$303.01 मिलियन) रहा।

CIN: U20299DL 1986NPL023253 | GST NO. 07AAACE1747M1ZJ PRESS RELEASE

SECRETARY TEXTILES LEADS A HIGH-LEVEL OUTREACH IN UNITED KINGDOM

EPCH ALONG WITH CEPC AND HEPC ORGANISED BUYER ENGAGEMENT PROGRAMME

CHAIRMAN EPCH URGES BUYERS FROM UK TO TAKE ADVANTAGE FROM INDIA - UK FTA

New Delhi/NCR – 22nd September'2025 – In the London, United Kingdom, Ms. Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textiles, Govt. of India met buyers and buying representatives. EPCH was represented by Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH and Mr. Rajesh Rawat, Addl. Executive Director EPCH. The objective of the meeting was to strengthen UK market access for Indian products by deepening buyer linkages through targeted G2G engagements, focused B2B meetings and roadshows informed Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH.

Ms. Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textiles, Govt. of India, while addressing the buyers, highlighted the significance of Indian textile sector in the overall exports from the country and stressed on the steps being taken with respect to design, sustainability, traceability, marketing initiatives by Govt. of India to promote the exports of textiles from the country. She urged all the buyers to take full advantage of the India-UK trade agreement which looks forward to a significant reduction to negligible duties on products exported between the countries.

Speaking on occasion, Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH, shared that "UK market demand offers a meaningful headroom for growth and the India–UK CETA helps us convert that potential into business through progressive tariff reductions, simpler rules of origin and smoother customs that translates into sharper UK price points and faster clearances for Indian suppliers.

Dr. Khanna further added that "Handicraft sector has deep concerns for stringent due-diligence requirements posing critical challenge for handicraft exporters, particularly MSMEs and artisan-based enterprises. We request a collaborative approach involving government bodies and industry stakeholders to develop a pragmatic compliance framework that protects our artisans while meeting global sustainability goal. We also appreciate the Textiles Secretary's patient hearing and look forward to working with the Ministry to leverage CETA opportunities while ensuring pragmatic, MSME-friendly compliance."

Mr. Rajesh Rawat, Addl. Executive Director EPCH said that "EPCH in collaboration with HEPC and CEPC organized an Interactive Session on the theme "India – A Profitable Destination for Sourcing Handicrafts, Handlooms and Carpets". Ms. Neelam Shami Rao graced the session as Chief Guest along with Ms. Shubhra, Trade Advisor, Ministry of Textiles; Mr. Kartikya Dhanda, Secretary, Textiles Committee; Mr. Amit Kumar, Director Trade. Ministry of Textiles; Ms. R Lalitha, Director Textiles, Govt. of Tamil Nadu; Dr. Neeraj Khanna, Chairman, EPCH; Mr. Lalit Goel, Chairman, HEPC; Mr. Kuldeep Wattal, Chairman, CEPC; Dr. Patricia Sumod, Head Domestic & International linkages, NIFT and other senior officials were present. The session brought together buyers and sourcing professionals to explore opportunities, align on market trends and reaffirming India's position as a trusted partner in the global handicrafts value chain."

Mr. Rawat further added "Buyers present at the occasion raised issues around logistics, intellectual property, design sensibilities, traceability, e-commerce, and other business aspects and expressed strong enthusiasm about leveraging the India–UK FTA".

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal institution for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million) and handicrafts exports to UK during 2024-25 was Rs 2562.70 crores (USD 303.01 Million), further informed by Mr. R. K. Verma, Executive Director-EPCH.

For more information please contact:

Mr. R. K. Verma, Executive Director, EPCH +91-9810679868

Encl: Hindi, English version and photos





Photo 1 & 2: Ms. Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textiles, Govt. of India met buyers at London, UK and EPCH was represented by Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH and Shri Rajesh Rawat, Addl. Executive Director EPCH.



Photo 3 & 4: EPCH in collaboration with HEPC and CEPC organized an Interactive Session on the theme "India – A Profitable Destination for Sourcing Handicrafts, Handlooms and Carpets". Ms. Neelam Shami Rao graced the session as Chief Guest along with Ms. Shubhra, Trade Advisor, Ministry of Textiles; Mr. Kartikya Dhanda, Secretary, Textiles Committee; Mr. Amit Kumar, Director Trade. Ministry of Textiles; Ms. R Lalitha, Director Textiles, Govt. of Tamil Nadu; Dr. Neeraj Khanna, Chairman, EPCH; Mr. Lalit Goel, Chairman, HEPC; Mr. Kuldeep Wattal, Chairman, CEPC; Mr. Rajesh Rawat, Addl. Executive Director, EPCH and Dr. Patricia Sumod, Head Domestic & International linkages, NIFT were present.